



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राप्तिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 116] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 1987/ज्येष्ठ 11, 1909

No. 116] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 1987/JYAISTHA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती हैं जिससे कि यह अक्षग संकलन के क्षण में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation.

बाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

मार्वेजनिक सूचना सं 182-प्राईटी सी (पी एन) /85—88

नई दिल्ली, 1 जून, 1987

विषय—प्राप्ति 1985—मार्च 1988 के लिए आयात नियंत्रण नीति

का न. 1/3/प्रार. इ. सी./85-ई. सी.—बाणिज्य मंत्रालय की मार्वेजनिक सूचना संख्या 1-प्राईटी सी (पी एन)/85—88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए यथासंशोधित आयात-नियंत्रण नीति की ओर ध्यान दियाया जाता है।

2 नीति में निम्नलिखित संशोधन नीति लिंक्स उपयुक्त स्थानों पर किए जाएँगे—

क्रम सं.	आयात-नियंत्रण नीति 1985—88 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	मंदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	292—293 (314—315)	परिशिष्ट-19 कर सूट स्कीम पेरा-29	(1) वर्तमान उप-मीरा (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा— ‘यदि कोई लाइसेंसधारी प्रत्यक्ष समय के भीतर, आहे पूर्ण या आधिक रूप में, निर्धारित नियंत्रण आजार को पूरा करने

1	2	3	4
			में ग्रामकाल रहता है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी आयात-नियांत्रित प्रक्रिया पुस्तक, 1985-88 के पैरा 350-क में उल्लिखित नियंत्रण के अनुभाव लाइसेंसधारी के विशेष कार्रवाई प्रारम्भ करेगा। लेकिन, यह कार्रवाई सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा सीमा शुल्क प्रधिनियम 1962 की धारा 142 के अधीन सीमा शुल्क कर या अन्य कर और उस पर व्याज की वसूली करने के लिए की गई किसी अन्य कार्रवाई को द्वारा में रखे बिना की जाएगी।'
		(2) उप पैरा-(3-क) में "उपर्युक्त उपचार -3" के अद्योतों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिलिपि द्वारा संशोधन नीति विविध उपर्युक्त स्थानों पर किए जाएंगे—	"आयात नियांत्रित प्रक्रिया पुस्तक, 1985-88 के पैरा 350-क"
		(3) उप-पैरा (4) को हटा दिया जाएगा।	

3 वाणिज्य मन्त्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 2-प्राई टी सी (पी एन)/85-88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अस्तर्गत प्रकाशित आयात नियांत्रित प्रक्रिया पुस्तक, 1985-88 की ओर भी द्वारा दिलाया जाता है। उपर्युक्त पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन नीति विविध उपर्युक्त स्थानों पर किए जाएंगे—

अम तं	आयात नियांत्रित प्रक्रिया पुस्तक, 1985-88 की पृष्ठ संख्या	संशोधन	संशोधन
1	2	3	4

1	65 (66)	प्रायाय-16 कर छूट स्कीम पद्ध-350	इस पैरे के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा— 350-क(1) यदि कोई लाइसेंसधारी बाहे पूरा या आंशिक रूप से विविध विविध आधार प्रूफ नहीं करता है और लाइसेंस प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कर छूट प्राप्त माल बेचा नहीं गया है या वेरेल्य उत्पादन के लिए उसका तुलन्योग नहीं किया गया है तो वरक्सेत्र प्राधिकारियों द्वारा कर छूट हकदारी प्रमाणपत्र को नियमित करने या मृत्त करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी—
---	------------	--	---

(क) यदि नियांत्रित भारतीय माल के अनुसार पूरा कर दिया गया है परन्तु मूल्य के अनुसार उसे करनी है तो लाइसेंसधारी का आयात नीति के परिविहित 17 के अनुसार किसी भी उत्पाद अमूल्य के वैध भार ही पीला लाइसेंस (मो)/हकदारी का उस मूल्य के बराबर प्रभारीण बरता पड़ेगा जो मूल्य के अनुसार लगाए गए और बास्तव में प्राप्त किए एसे नियांत्रित भारतीय का अनुसार है।

(ब) यदि नियांत्रित भारतीय मूल्य के अनुसार पूरा कर दिया गया है परन्तु केवल माल के अनुसार उसे करनी है तो लाइसेंसधारी को निम्नलिखित अपेक्षित होंगा—

(1) जिस आधार पर अनुसोदित निवेश-उत्पाद मन्त्रपत्रों ने अनुसार छूट माल की उस माल पर जो असमुपयोजित मान दिया गया है, 18 प्रतिशत व्याज के सहित सीमांतर का प्राधिकारियों को सभी शुल्कों का मुग्धतान करना, और

(2) यदि आयात की सभी अवधार कुछ भवे बापती की नारीब को बाये मायाव्य लाइसेंस के प्रधीन से भिन्न अमरुल्याजित रहे अधिक माल के लागत-बीमा-भाड़ा भव्य के समतुल्य हकदारी/बीमा भार ही पीला लाइसेंस को बापत करना। लेकिन आर ही पीला लाइसेंस/हकदारी की बापती इसी नियांत्रित उत्पाद वर्ग के लिए हो। यदि यह कभी 10 प्रतिशत तक हो और यदि यह 10 प्रतिशत से अधिक हो तो आयात नीति के परिविहित 17 की इसी क्रमांक में अद्यवा उपक्रम में के लिए हो।

(ग) यदि लाइसेंसधारक माला और मूल्य दातों में ही निर्धारित आधार पूरा करने में असमर्थ है तो उसको निम्न प्रवेशित होगा --

(1) जिस आधार पर अनुमोदित निवेश-उत्पाद मानदण्डों के अनुमान छूट मात्र की उम माला पर अत्युपयोगित मान लिया गया है, 18 प्रतिशत व्याज के महिने सीमांगु-क्र प्राधिकारियों को मसी भूक्ती का भुगतान करना, और

(2) उपर्युक्त पैरा (ब) (2) के अनुमान वेष्ट आरईपी/लाइसेंस हक्कवारी बापत करने के लिए और इसको अनिवार्य मूल्य में ह्रास के लिए उपर्युक्त पैरा (क) के अनुसार।

(2) उपर्युक्त उप पैरा (1) में उल्लिखित मामलों में, यदि लाइसेंसधारक लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा तीन महीने की अवधि के दौरान अवकाश निर्धारित आपूर्क द्वारा इस प्रकार से बढ़ाई गई अवधि के दौरान उपर्युक्त कार्रवाई करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा निष्पादित बाणी/विधिक करार लागू किया जाए। लाइसेंसधारक इस प्रकार चूककर्ता घोषित किया जाए जिससे कि वह इन सीमित सहित नीनि के किसी भी प्रावधान के प्रतीक्षा उसके कोई भी लाइसेंस/रिलीज आदेश प्राप्त करने का कोई हक न हो। यदि लाइसेंसधारक उपर्युक्त उप पैरा (1) में निहित जातों का अनुपालन करता है तो लाइसेंसधारक को चूककर्ता घोषित करने का आदेश लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा बापत लिया जाए। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा सीमांगु-क नथा उग पर देय व्याज यदि कोई हो तो उसका समाप्तीजन जब्त की गई बैंक गारण्टी से किया जाएगा। उन मामलों में जहाँ कोई बैंक गारण्टी नहीं दी गई है या बैंक गारण्टी की राशि देय राशि के बसूल करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो लाइसेंसधारी को देय नियंत्रित प्रोत्साहनों में से कटीनिया करके बसूल भी जाए। लाइसेंस प्राधिकारी नियंत्रित की गई ही पी एक्सेस जो भी अनियंत्रित की गई हो या उपर्युक्त उप पैरा (1) के अनुमति में अन्यथा की गई हो को उन लकड़ी-से की माला क यहें अविकल्प वे अंगि की जाए को भी समर्जित किया जाए।

(3) उन मामलों में जहाँ लाइसेंस प्राधिकारी सतुष्ट हो कि नियंत्रित आधार वा प्रतिपूर्ति की असकलता का कारण नियंत्रित की कोई भूल या कोई लापन्नाही है वहा नियंत्रित द्वारा निष्पादित किया गया इच्छ/विधिक कलशर को नागू किया जाएगा। लाइसेंस प्राधिकारी उपर्युक्त उप पैरा (1) के समुदार की गई कार्रवाई के अनिवार्य आयात नथा नियंत्रित नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत उपर्युक्त वित्तीय दस्त दे सकते हैं।

(4) जहाँ लाइसेंसिंग प्राधिकारी सतुष्ट है कि कृष्ट प्राप्त माल भेजा गया है या स्वेच्छी उप्यादनों के लिए इसका दुरुपयोग किया गया है यहा उल्लिखित प्राधिकारी उपर्युक्त उप पैरा (3) में उल्लिखित के अनिवार्य वर्जित करके या आयात नथा नियंत्रित नियंत्रण अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत जारी आदेशों के अन्तर्गत अभियोजन के द्वारा बारेतारी करे। इस मामलों से आण्ड का निष्पालन सीमांगु-क नथा इस पर देय व्याज की राशि अनिवार्य के होगा। लाइसेंसधारक को चूककर्ता घोषित करेगा और उसको इस नीनि वे अन्तर्गत इस स्थिर के महित इससे लाइसेंस/रिलीज आदेश को हकदारी से बियुक्त कर दिया जाएगा।

(5) उपर्युक्त उप पैराग्राफों में उल्लिखित को द्यान में रखे बिना, मूल्य नियंत्रण, आयात-नियंत्रित किसी भी मायने की पुनरीक्षा कर सकते हैं और उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

6. उपर्युक्त संशोधन सोकहित में किए गए हैं।

7. कालम (2) में कोष्ठक में उन्निवेश सदस्य संशोधित आयात-निर्यात नीति पुस्तक और आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक, 1985-88 की पृष्ठ संख्या को दर्शाने हैं।

ह. /-

राजीव लोकत मिश्र,
मुख्य नियंत्रक, आयात नियंत्रित
प्रतिष्ठा सोहन, उप मुख्य नियंत्रक, आयात नियंत्रित
इते मुख्य नियंत्रक, आयात नियंत्रित।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 182-ITC(PN)/85-88

New Delhi, the 1st June, 1987

Subject : Import & Export Policy for April 1985—March, 1988

F. No. 1/3/REP/85-EPC :—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985—March, 1988 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1—ITC (PN)/85—88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendments shall be made in the policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy 1985-88 (Vol. I)	Reference	Amendment			
			1	2	3	4
1.	292-293 (314-315)	APPENDIX 19. : DUTY EXEMPTION SCHEME, PARA 29	(i)	The existing sub-para (3) shall be substituted by the following :		
				"(3) If a licence holder fails to discharge the prescribed Export Obligation within the permitted time, either in full or in part, the licensing authorities shall initiate action against the licence holder on the lines indicated in Para 350-A of Chapter XVI of the Hand Book of Import Export Procedures, 1985—88. This action shall, however, be without prejudice to any action that may be initiated by the Customs authorities for recovery of Customs duty or other duties and interest thereon under Section 142 of the Customs Act, 1962."		
			(ii)	In sub-para (3-A), the words "sub-para 3 above" shall be substituted by the following :		
				"Para 350-A of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1985—88".		
			(iii)	Sub-para (4) shall be deleted.		

3. Attention is also invited to the Hand Book of Import-Export Procedures 1985—88, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC (PN)/85-88 dated the 12th April, 1985. The following amendments shall be made in the said Hand Book at the appropriate places as indicated below :

Sl. No.	Page No. of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1985—88	Reference	Amendments
1	2	3	4
1.	65 (65)	CHAPTER XVI DUTY EXEMPTION SCHEME PARA — 350	<p>After this para, the following new para shall be added :—</p> <p>“350-A (1). If a licence holder fails to discharge the prescribed Export Obligation, either in full or in part and the licensing authority is satisfied that the exempt material has not been sold or misutilised for domestic production, the following action may be taken by the licensing authorities to regularise and discharge the DEEC :—</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) If the export obligation has been fulfilled in terms of quantity but there is a shortfall in terms of value, the licence holder shall be required to surrender valid REP licence(s) entitlement of any product group as per Appendix 17 of the Import Policy, for a value equivalent to the difference in the export obligation imposed and actually achieved in value terms. (b) If the export obligation has been fulfilled in terms of value but there is a shortfall only in terms of quality, the licence holder shall be required— <ul style="list-style-type: none"> (i) to pay to the Customs Authorities all duties along-with 18% interest on such quantity of the exempt materials as are deemed to have remained unutilised as per approved input-output norms on the basis of which the licence was issued, and (ii) to surrender valid REP licence/entitlement equivalent to the CIF value of the excess material left unutilised if all or some of the items of import were other than those under OGL on the date of surrender. However, the surrender of REP licence/entitlement may be for the same export product group, if the shortfall is upto 10% and for the same Sl. No. or sub-Sl. No. of Appendix 17 of the Import Policy, if it is more than 10%. (c) If the licence holder is not able to fulfil the export obligation both in terms of quantity and value, he shall be required— <ul style="list-style-type: none"> (i) to pay to the Customs Authorities all duties along-with 18% interest on such quantity of the exempt materials as are deemed to have remained unutilised as per approved input-output norms on the basis of which the licence was issued; and (ii) For the shortfall in quantity to surrender valid REP licence/entitlement as per (b)(ii) above and in addition for the shortfall in value, as per (a) above. (2) In cases referred to sub-para (1) above, if the licence holder fails to act as above when directed by the licensing authority within a period of 3 months or such further period as extended by the Export Commissioner, the bond/legal agreement executed by him may be enforced. The licenceholder may be declared a defaulter thereby disentitling him to secure any licences/release orders under any provisions of the policy including this scheme. The order declaring the licensee defaulter

(1)	(2)	(3)	(4)
			may be withdrawn by the licensing authority on the licensee fulfilling the conditions prescribed in sub para (1) above. The Customs duties and the interest payable thereon would be adjusted from the forfeited Bank Guarantee, if any, by the licensing authority. In cases where no Bank Guarantee has been furnished or the amount of the Bank Guarantee is not sufficient to cover the amount payable, recovery may be made from the export incentives due to the licence holder. The licensing authority may also adjust the REP entitlement of the exporter which might have been earned or may be earned in future against the quantum of such licences to be surrendered as per sub-para (1) above.
			(3) In cases where the licensing authority is satisfied that the failure in the fulfilment of the export obligation has been on account of any lapse or any slackness on the part of exporter, the bond/legal agreement executed by the exporter shall be enforced. The licensing authority in addition to taking action in sub para (1) above may also impose a suitable fiscal penalty under the Import Export Control Act.
			(4) Where the licensing authority is satisfied that the exempt material has been sold or misutilised by diverting it for domestic production, the said authority shall take action for debarment and prosecution under the Import & Export Control Act and Orders issued thereunder in addition to the action enumerated in sub para (3) above. In such cases the enforcement of the bond would be in addition to the recovery of customs duty and interest thereon. The licensee shall be declared a defaulter disentitling him to any licences/release orders under the Policy including this Scheme.
			(5) Notwithstanding any thing contained in the above sub-paragraphs, the Chief Controller of Imports and Exports may review any case and pass appropriate orders.

6. The above amendments have been made in Public interest.

7. The number in bracket in Column (2) indicate the page number in the amended Import-Export Policy Book and Hand Book of Import-Export Procedures, 1985-88.

Sd/-

(R. L. MISRA)

Chief Controller of Imports and Exports

P. MOHAN, Dy. Chief Controller of Imports and Exports
For Chief Controller of Imports and Exports